(पूरा बेंच)

माननीय एम. *आर.* अग्निहोत्री, *ए. एस. नेहरा और एन. के. सोधी, जे. जे. के समक्ष*

मीनाक्षी शर्मा - याचिकाकर्ता।

बनाम

स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा, भिवानी अन्य, -उत्तरदाता।

Civil Writ Petition No. 1802 *of* 1992

21st July, 1992

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1969- धारा 19- हरियाणा *विद्यालय* शिक्षा *बोर्ड विनियम- विनियमन 26—कम्पार्टमेंट परीक्षा में अनुग्रह अंकों* का *अनुदान- अनुग्रह अंकों का आवंटन- विनियमन की वैधता- विनियमन मनमाना या अन्यायपूर्ण।*

माना गया कि विनियमन में प्रावधान है कि कम्पार्टमेंट परीक्षा में बैठने वाला उम्मीदवार अनुग्रह अंकों के रूप में विषय को आवंटित अधिकतम अंकों के 1 प्रतिशत के लिए पात्र होगा।

(पैरा 7)

(14 दिसंबर, 1992 *को* पंजाब *और हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा निर्णय लिया गया* C.W.P. No. 13981 of 1991)

(सही ठहराया)

अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त विनियम में कोई संवैधानिक या कानूनी दुर्बलता या कोई मनमानी नहीं है। सफलता प्राप्त करने की आवश्यकता के माध्यम से विधायिका और कानून का उद्देश्य केवल छात्रों के शिक्षा के हित को, उनके अपने प्रदर्शन के आधार पर, बढ़ावा देना था। जाँच करने वाले निकाय की कृपा के आधार पर नहीं। ।अनुग्रह अंक प्रदान करने का अंतर्निहित उद्देश्य एक ऐसे उम्मीदवार के लिए वास्तविक कठिनाई को दूर करना है जिसने अन्यथा विद्या सम्बन्धी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन किसी तरह एक या दो विषयों में एक या दो अंकों की कमी के कारण अपने शैक्षिक जीवन का एक वर्ष खो रहा है, जबकि अन्य विषयों में अपने समग्र प्रदर्शन के आधार पर, वह सफल घोषित होने का हकदार है।यह विचार प्रशंसनीय होने के कारण, विनियमन 26 न तो मनमाना है और न ही अनुचित या अन्यायपूर्ण है।

(पैरा 7)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के *तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि:*

(i) परमादेश की प्रकृति का एक रिट जिसमें *प्रतिवादी को निर्देश दिया गया है कि वे*

याचिकाकर्ता को विनियमन *26 के अनुसार 4 अनुग्रह* अंकों *का लाभ* दें, *जो परीक्षा उत्तीर्ण करने की कमी को पूरा करने* के *लिए अंग्रेजी कोर विषय में 5 विषयों को आवंटित कुल कुल अंकों के 1 प्रतिशत के बराबर है।*

(ii) परमादेश की प्रकृति का एक रिट जिसमें *प्रतिवादी संख्या 1 से* 3 को हरियाणा स्कूल *शिक्षा बोर्ड वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा 1990 में उत्तीर्ण घोषित करने और परिणाम* कार्ड/प्रमाण *पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया हो;*

(यू. आई.) सरशियोरेराई प्रकृति में एक रिट जो यह घोषणा करती है कि वार्षिक और पूरक (कम्पार्टमेंट) परीक्षा के लिए विभिन्न अनुग्रह अंक प्रदान करने के लिए वर्गीकरण अवास्तविक अति-तकनीकी है और बिना किसी अच्छे उद्देश्य के है और उसे निरस्त किया जा सकता है;

(iv) कोई अन्य रिट/आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में उचित और उचित समझे;

(v) अनुलग्नक की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने और प्रतिवादी को अग्रिम सूचना देने से छूट दी जा सकती है।

(vi) रिट याचिका को लागत के साथ अनुमति दी जा सकती है।

अंतरिम राहत के लिए प्रार्थनाः यह प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादी को इस रिट याचिका के निर्णय के लंबित रहने तक विषय अंग्रेजी कोर में *4 अंक देकर याचिकाकर्ता का परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया जा सकता है।*

(माननीय न्यायाधीश श्री ए. पी. चौधरी और माननीय न्यायाधीश श्री एन. सी. जैन की पीठ ने 12 मार्च, 1992 को C.W.P. No. 13981 of 1991 *के साथ एक बड़ी पीठ को इन मामलों में शामिल कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए भेजा था (14 फरवरी, 1992 को खण्ड पीठ* द्वारा निर्णय लिया *गया) इन मामलों में शामिल कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न। माननीय न्यायाधीश श्री एम. आर. अग्निहोत्री, माननीय न्यायाधीश श्री ए. एस. नेहरा और माननीय न्यायाधीश श्री एन. के. सोधी की पूर्ण पीठ ने अंततः रिट याचिका को खारिज कर दिया और 21 जुलाई, 1992 को* 1991 *C.W.P. No.* 13981 *of* 1991 की पुष्टि की।

ए. के. कुलश्रेष्ठ, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से

श्रीमती *आभा* राठौर, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से *3 के लिए*

वरिष्ठ अधिवक्ता एस. सी. सिब्बल, अधिवक्ता दीपक *सिब्बल के साथ,* प्रतिवादी संख्या 4 के लिए

निर्णय

एम *आर अग्निहोत्री, जे।*

■याचिकाकर्ता मार्च, 1990 में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा में उपस्थित हुए।परीक्षा में पांच विषय शामिल थे, प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक थे, जिसमें न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 33 था।पाँच विषयों में से, याचिकाकर्ता केवल चार विषयों को पास कर सका और उसे अंग्रेजी कोर विषय में *कम्पार्टमेंट* में रखा गया। अपने कम्पार्टमेंट को पास करने के लिए, याचिकाकर्ता सितंबर, 1990 के महीने में पूरक परीक्षा और मार्च, 1991 में आयोजित अगली वार्षिक परीक्षा में उपस्थित होकर दो अवसरों का लाभ उठा सकती थी।याचिकाकर्ता ने पहले मौके का लाभ उठाया लेकिन कम्पार्टमेंट को पार नहीं कर सके।जब वह मार्च, 1991 में दूसरी बार उपस्थित हुईं, तो उन्हें फिर से अंग्रेजी कोर के विषय में कम्पार्टमेंट में रखा गया, क्योंकि उन्होंने 100 में से केवल 29

अंक प्राप्त किए थे, जबकि उत्तीर्ण प्रतिशत 33 था।

इस स्थिति में याचिकाकर्ता की शिकायत है कि उसने अंग्रेजी कोर विषय में 100 अंकों में से 29 अंक प्राप्त किए थे, यानी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत से केवल चार अंक कम। उसे कम्पार्टमेंट में नहीं रखा जाना चाहिए था, बल्कि अनुग्रह के रूप में चार अंक जोड़कर सफल घोषित किया जाना चाहिए था।दावा स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा के विनियमों के विनियम 26 पर आधारित है, जिसके अनुसार यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक विषयों में विफल रहता है और कुल कमी कुल अंकों के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो उस उम्मीदवार को विषय को आवंटित अंकों के 1 प्रतिशत की सीमा तक कम्पार्टमेंट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अनुग्रह अंक दिए जाएंगे।याचिकाकर्ता के अनुसार विषय को आवंटित अधिकतम अंकों का 1 प्रतिशत, सभी पांच विषयों (यानी पांच अंक) के कुल कुल अंकों का 1 प्रतिशत होना चाहिए और इसलिए, उसे सफल घोषित होना चाहिए क्योंकि उसके लिए आवश्यक अनुग्रह अंक केवल चार थे। वैकल्पिक रूप से, यदि विनियमन की व्याख्या अन्यथा की जानी थी, अर्थात, अनुग्रह अंकों के अनुदान को संबंधित विषय को आवंटित अधिकतम अंकों के केवल 1 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए, तो विनियमन मनमाना था और निरस्त होने योग्य था।

(2) हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा दाखिल किए गए विवरण में यह रुख अपनाया गया है कि कम्पार्टमेंट उम्मीदवार को अनुग्रह अंक देने की सीमा संबंधित विषय को आवंटित अधिकतम अंकों के केवल 1 प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिए, यानी वह विषय जिसमें उम्मीदवार को कम्पार्टमेंट में रखा गया था।इसके लिए, 14 फरवरी, 1992 के 1991 के C.W.P. No. 13981 of 1991 में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया था, जिसमें यही दृष्टिकोण लिया गया है।

(3) प्रस्ताव पीठ ने 12 मार्च, 1992 को एक पूर्ण पीठ के समक्ष रिट याचिका को स्वीकार कर लिया क्योंकि इसका विचार था कि उपरोक्त खण्ड पीठ के फैसले पर आगे विचार करने की आवश्यकता है।तदनुसार, हमने एक बार फिर फैसले पर विचार किया है, और उसमें लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन करने में कोई संकोच नहीं है।

(4) 10+3 की कम्पार्टमेंट परीक्षा में अनुग्रह अंकों का अनुदान हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एक्ट, 1969 की धारा 19 के तहत स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा द्वारा बनाए गए विनियमों के विनियमन 26 द्वारा नियंत्रित किया जाता है।यह विनियमन प्रदान करता है कि कम्पार्टमेंट परीक्षा में उपस्थित होने वाला उम्मीदवार अनुग्रह अंकों के रूप में विषय को आवंटित अधिकतम अंकों के 1 प्रतिशत के लिए पात्र होगा।विनियम 26 (ए) नियमित जांच से संबंधित है, जबकि विनियम 26 (बी) केवल कम्पार्टमेंट मामले से संबंधित है।ये दोनों

प्रावधान स्वतंत्र और परस्पर अनन्य हैं।विनियम 26 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः—

"26. ग्रेस मार्क्स।

(a) यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक विषयों में विफल रहता है और कुल कमी कुल अंकों के एक प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो उसे आवश्यक अनुग्रह अंक (जो किसी भी संख्या में विषयों के बीच वितरित किए जा सकते हैं) प्रदान किए जाएंगे, बशर्ते व्यावहारिक परीक्षा में दिए गए अनुग्रह अंक व्यावहारिक परीक्षा में उम्मीदवार द्वारा वास्तव में प्राप्त अंकों से अधिक न हों।

(b) एक उम्मीदवार कम्पार्टमेंट अर्जित करने के लिए अनुग्रह अंकों के लाभ का हकदार नहीं होगा, हालांकि वह हकदार होगा

परीक्षा के लिए आवंटित अधिकतम अंकों के एक प्रतिशत की सीमा तक कम्पार्टमेंट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अनुग्रह अंक।

(c) अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार के लिए किसी विषय में उपस्थित होने वाला उम्मीदवार अनुग्रह अंकों का हकदार नहीं होगा।

(d) एक या अधिक अतिरिक्त विषयों में उपस्थित होने वाला उम्मीदवार भी पेपरों को आवंटित कुल अंकों के कुल एक प्रतिशत तक अनुग्रह अंकों के लिए पात्र होगा।

(6) संयोग से, यह मामला ***पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ बनाम श्री सुंदर सिंह***[1] के रूप में रिपोर्ट *किए गए माननीय* सर्वोच्च *न्यायालय के फैसले* द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है, जिसमें लॉर्डशिप पंजाब विश्वविद्यालय विनियमों के नियम 27 की व्याख्या कर रहे *थे* जो बिल्कुल समान प्रश्न से संबंधित थे।नियम 27 निम्नानुसार हैः—

" 27.1 (क) एक उम्मीदवार जो परीक्षा के सभी विषयों में उपस्थित होता है और जो एक या एक से अधिक विषयों (लिखित, व्यावहारिक, *सत्रीय* या मौखिक) और/या कुल में विफल रहता है, यदि कुल मिलाकर उत्तीर्ण होने की अलग आवश्यकता है, तो कुल कुल अंकों (आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को छोड़कर) के अधिकतम 1 प्रतिशत तक अनुग्रह अंक दिए जाएंगे ताकि कमी को पूरा किया जा सके यदि उम्मीदवार इस तरह के जोड़ से परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। अनुग्रह अंक प्रदान करते समय, ए या उससे अधिक पर काम करने वाले अंश को पूरे के के समान माना जाएगाः

बशर्ते कि किसी उम्मीदवार को अनुग्रह अंक भी दिए जाएं यदि ऐसे अंक देकर वह विषय/विषयों और भाग/विषयों में छूट या कम्पार्टमेंट अर्जित कर सकता है।

[1] A.T.R. 1984 S.C. 919.

(बी) एक उम्मीदवार जो उस कम्पार्टमेंट या विषयों और भागों को पास करने के लिए फिर से उपस्थित होता है जिसमें उसे फिर से उपस्थित होने के लिए (योग्य) घोषित किया गया है, उसे उस विषय के कुल अंकों का 1 प्रतिशत तक अनुग्रह अंक प्रदान किया जाएगा जिसमें वह फिर से उपस्थित होता है यदि इस तरह के जोड़ से उम्मीदवार उस विषय या भाग में उत्तीर्ण हो सकता है।"

उपरोक्त प्रावधानों की व्याख्या करते समय, सर्वोच्च न्यायालय के उनके संरक्षकों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि—

" खंड (बी) में प्रावधान स्पष्ट है और उम्मीदवार फिर से उपस्थित होने पर जिस विषय/विषय में वह फिर से उपस्थित होता है, उसके कुल अंकों का एक प्रतिशत अनुग्रह अंकों का हकदार हो जाता है। एक बार खंड (बी) लागू होने के बाद, पहले ली गई नियमित परीक्षा में प्रदर्शन के लिए कोई संदर्भ उपलब्ध नहीं है और इंगित सीमा तक अनुग्रह अंकों का लाभ पुनः उपस्थिति में प्रदर्शन तक ही सीमित होना चाहिए।"

इसलिए, यह विवाद कि क्या एक उम्मीदवार जिसे कम्पार्टमेंट में रखा गया है, वह विषय के कुल कुल अंकों के 1 प्रतिशत तक अनुग्रह अंक देने का हकदार है, या अकेले उस विषय के अधिकतम अंकों के 1 प्रतिशत की सीमा तक, जिसमें उम्मीदवार को कम्पार्टमेंट में रखा गया

है, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से पहले ही समाप्त हो चुका है।परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता का दावा किसी भी बल से रहित है और अस्वीकार किए जाने योग्य है।वास्तव में C.W.P. No. 13981 of 19911 में इस न्यायालय के उपरोक्त खण्ड पीठ के फैसले ने केवल ***श्री सुंदर सिंह के मामले*** (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, जो *बाध्यकारी होने के साथ-साथ* निर्णायक भी है।

(7) जहाँ तक विनियमन 26 को *चुनौती* देने का संबंध है, हम उक्त विनियमन में कोई संवैधानिक या कानूनी दुर्बलता या कोई मनमानेपन नहीं पाते हैं।जाहिर है, विधानमंडल और विधान का उद्देश्य केवल छात्रों को अपने स्वयं के प्रदर्शन के आधार पर परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की आवश्यकता देकर शिक्षा के हित को बढ़ावा देना था, न कि परीक्षा निकायों की कृपा पर निर्भर करना।अनुग्रह अंक प्रदान करने का अंतर्निहित उद्देश्य एक ऐसे उम्मीदवार के लिए वास्तविक कठिनाई को दूर करना है जिसने अन्यथा विद्या सम्बन्धी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन किसी तरह एक या दो विषयों में एक या दो अंकों की कमी के कारण अपने शैक्षिक जीवन का एक वर्ष खो रहा है, जबकि अन्य विषयों में अपने समग्र प्रदर्शन के आधार पर, वह सफल घोषित होने का हकदार है।यह विचार प्रशंसनीय होने के कारण, विनियमन 26 न तो मनमाना है और न ही अनुचित या अन्यायपूर्ण है।"वास्तव में, यह शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता पर *जोर* देना चाहता है, इसलिए इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

(8) नतीजतन, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है और 1991 (ऊपर) के C.W.P. No. 13981 of 1991 में इस न्यायालय के खण्ड पीठ के फैसले की पुष्टि की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

विनीत कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा